अमर उजाला

स्पेक्ट्रम नीलामी : 15 अगस्त से शुरू हो सकती हैं 5जी सेवाएं, दूरसंचार विभाग ने ट्राई से मार्च से पहले मांगी सिफारिशें

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Sat, 26 Feb 2022 06:34 AM IST

सार

सरकार का इस साल 15 अगस्त तक 5जी सेवाओं की शुरुआत करने का इरादा है। दूरसंचार विभाग 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इससे जुड़ी शर्तें एवं प्रावधान ट्राई की अनुशंसा के बाद ही तय होंगे। नीलामी में 526-698 मेगाहर्ट्ज व मिलीमीटर बैंड जैसी नई फ्रीक्वेंसी के लिए मानदंड तय किए जा रहे हैं।

5G - फोटो : pixabay

विस्तार

देश में 5जी सेवाओं की शुरुआत 15 अगस्त से हो सकती है। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने ट्राई से 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़ी शर्तों के बारे में अनुशंसा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ मार्च 2022 के पहले सिफारिशें सौंपने का अनुरोध किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सचिव को लिखे पत्र में विभाग ने कहा, 5जी स्पेक्ट्रम की दरों एवं शर्तों के बारे में अनुशंसा जल्द दी जाए।

सरकार का इस साल 15 अगस्त तक 5जी सेवाओं की शुरुआत करने का इरादा है। दूरसंचार विभाग 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इससे जुड़ी शर्तें एवं प्रावधान ट्राई की अनुशंसा के बाद ही तय होंगे। नीलामी में 526-698 मेगाहर्ट्ज व मिलीमीटर बैंड जैसी नई फ्रीक्वेंसी के लिए मानदंड तय किए जा रहे हैं।

इसके अलावा 700 मेगाहर्ट्ज, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 व 3300-3670 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए भी बोली लगाई जाएंगी। 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़े हितधारकों से विमर्श के लिए ट्राई ने हाल ही में चर्चा आयोजित की थी। इसके बाद दूरसंचार नियामक अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप देने में जुट गया है।

शर्त के साथ इंडस टावर्स में 4.7 फीसदी हिस्सा खरीदेगी एयरटेल

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने शुक्रवार को कहा कि उसने इंडस टावर्स में वोडाफोन की 4.7 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया है। समझौता इस शर्त के साथ है कि इस राशि का इस्तेमाल वोडाफोन आइडिया में निवेश करने व मोबाइल टावर कंपनी का बकाया चुकाने में होगा। कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया इंडस टावर्स के बकाए का भुगतान करने में असमसर्थ रही है। वोडाफोन आइडिया और प्रवर्तक कंपनी वोडाफोन दोनों ने 15 जुलाई 2022 तक बकाया चुकाने के लिए एक भुगतान योजना का प्रस्ताव रखा है।